

प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों का सर्वशिक्षा अभियान के सन्दर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन

सारांश

शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास की धुरी होती है। आज सम्पूर्ण विश्व का ध्यान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की तरफ केन्द्रित है। जीवनोपयोगी एवं गुणवत्तापरक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा आज सम्पूर्ण विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक एवं भौतिक संसाधन प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अभिन्न अंग हैं। वर्तमान अध्ययन में सर्वशिक्षा अभियान के सन्दर्भ में जिला हाथरस के प्राथमिक विद्यालयों की संगठनात्मक एवं भौतिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु 50 विद्यालयों का न्यादर्श के रूप में चयन स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि के द्वारा किया गया। आकड़ों के एकत्रीकरण के लिए स्व-निर्मित अवलोकन सूची का निर्माण किया गया। जिसमें भौतिक एवं शैक्षिक संसाधन उपलब्धता के 15 बिन्दुओं के आधार पर अवलोकन सूची का निर्माण किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया। अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधा के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, खेल के मैदान की उत्तम व्यवस्था पाई गई जबकि विद्यालय भवनों, प्रकाश की व्यवस्था, फर्नीचर व्यवस्था, संवातन हेतु सुविधा, मध्याह्न भोजन व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय निम्न स्थिति के पाए गए। शैक्षिक सुविधाओं से सम्बन्धित उपलब्धियों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि—परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधा के अन्तर्गत श्यामपट्ट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सुविधा उत्तम पाई गई व शिक्षक छात्र अनुपात शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तकालय व्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति निम्न पाई गई। भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं से सम्बन्धित उपलब्धियों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि— अधिकांश प्राथमिक विद्यालय निम्न स्तर के हैं। शहरी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, अर्द्धशहरी व ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति से बेहतर है व अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों से बेहतर है।

मुख्य शब्द : सर्वशिक्षा अभियान, प्राथमिक विद्यालय, भौतिक संसाधन, शैक्षिक सुविधा।

प्रस्तावना

शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक शिक्षा पर ही राष्ट्र की माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा निर्भर करती है। प्रयोगात्मक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति का आधार वहाँ की प्राथमिक शिक्षा ही है।

प्रत्येक व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन प्राथमिक शिक्षा पर ही आधारित होता है, क्योंकि उसके सम्पूर्ण जीवन की नींव प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ही डाली जाती है। यह नींव जितनी अधिक मजबूत होगी उसका जीवन उतना ही खुशहाल और सम्पन्न होगा। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर देते हुये संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत यह घोषणा की गई कि "संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि के अन्दर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा"। परन्तु देश के सामने यह समस्या थी कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा कैसे सर्वसुलभ करायी जाए? अर्थात् प्राथमिक शिक्षा का देश में सार्वभौमिकरण कैसे किया जाए ? इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया गया।

देवेन्द्र सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
हेमवती नन्दन बहुगुणा
गढ़वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय),
बिड़ला परिसर,
श्रीनगर (गढ़वाल),
उत्तराखण्ड

मुरारी सिंह यादव

शोध छात्र,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
हेमवती नन्दन बहुगुणा
गढ़वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय),
बिड़ला परिसर,
श्रीनगर (गढ़वाल),
उत्तराखण्ड

संजीव कुमार

शोध छात्र,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
हेमवती नन्दन बहुगुणा
गढ़वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय),
बिड़ला परिसर,
श्रीनगर (गढ़वाल),
उत्तराखण्ड

E: ISSN No. 2349-9435

देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक योजनायें चलाई गयीं। जिसमें प्रमुख— जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), आपरेशन ब्लैक बोर्ड (1988), मध्याह्न भोजन योजना (1998), शिक्षाकर्मि योजना, शिक्षा गारंटी योजना, लोक जुम्बिश परियोजना (1972), जनशाला, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा आदि हैं।

सन् 2001-2002 से देश में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की भागीदारी और संयुक्त प्रयास के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। इसी सन्दर्भ में सर्वशिक्षा अभियान में कुछ समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जिसमें 2002 तक देश के सभी जिलों में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम पहुँचाना, 2003 तक देश के सभी बच्चों को स्कूल, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालयों में लाना तथा 2007 तक 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना।

न्यूपा (NUEPA) की सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किया गया है कि— देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ सभी प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक एवं शैक्षिक साधन उपलब्ध हों। शिक्षा के इस संकट को ध्यान में रखते हुये योजना आयोग (नीति आयोग) ने सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूली शिक्षा के स्तर को उठाने और प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार एवं सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करोड़ों रुपये का बजट स्वीकार किया है। परन्तु इन प्रयासों के बाद भी विद्यालयों की स्थिति में सापेक्षित विकास नहीं हो रहा है और न ही सार्वभौमीकरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं। अतः यह जानना आवश्यक है कि प्राथमिक विद्यालय सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं या नहीं और इस अभियान के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं। यह जानने के लिये एवं 'सर्वशिक्षा अभियान' के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों की स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन के तहत इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया गया है।

साहित्यावलोकन

काण्डपाल, के0 (2015), ने अपने अध्ययन जनपद बागेश्वर में पारंपरिक शिक्षा की दशा एवं दिशा (शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में) पाया कि विद्यार्थियों तथा अभिभावकों में सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर सजगता है। शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक चेतना एवं सक्रियता का अभाव दिखाई देता है। सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों में बालकों की तुलना में बालिकाओं का प्रतिशत अधिक है। इससे यह अनुमान मिलता है कि बालकों का नामांकन निजी विद्यालयों में जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। 25 % सरकारी विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। 50 % सरकारी विद्यालयों में स्वच्छ एवं

Periodic Research

सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता है। सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 23:1 है। वर्मा, वी0के0 (2014), ने अपने अध्ययन सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति का अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति अभिभावकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है। पुरुष अभिभावक, महिला अभिभावकों की तुलना में तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के पुरुष सदस्य महिला सदस्यों की तुलना में अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। सिंह, एन0 (2013), ने अपने अध्ययन सर्व शिक्षा अभियान के मौलिक सिद्धान्तों एवं राष्ट्र के निर्माण में उसका योगदान में निष्कर्ष निकाला कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षा की गुणात्मक उन्नयन तथा सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को बताते हुए सर्व शिक्षा अभियान किस प्रकार राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहा है तथा उसके मुख्य प्रावधानों का उल्लेख किया जिसमें— लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता, पहुँच और समानता सुनिश्चित करना, विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक नियुक्ति और प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का नवीनीकरण, सामुदायिक भागीदारी आदि प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। त्रिपाठी, वी0एन0 एवं अमन, ए0के0 (2012) ने अपने अध्ययन सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त विशेष अध्यापकों का विकलांग बालकों की शिक्षा में योगदान में निष्कर्ष निकाला कि 75 % अध्यापक मानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान विकलांग बालकों के लिए एक सार्थक प्रयास है। 85 % अध्यापकों का मानना है कि विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षकों को संवेदनशील होना चाहिए। 80 % अध्यापकों का मानना है कि विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक है। 45 % बालकों का मानना है कि उनके अध्यापक उनसे भावनात्मक लगाव रखते हैं। 75 % बालकों का मानना है कि उनका विद्यालय का वातावरण उनके अनुकूल है। चन्द्र, एन0 (2011), ने अपने अध्ययन प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रभावकारिता के अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिक विद्यालयों में संचालित योजनाओं का प्रभाव शिक्षार्थियों की उपलब्धि, शिक्षकों में रुचि व अभिभावकों में जागरूकता के रूप में पाया गया। विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के प्रति ग्रामीण एवं शहरी दोनों अभिभावक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। विद्यालय वातावरण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों का विचार नकारात्मक पाया गया। शर्मा, के0 (2005) ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि केवल 48 प्रतिशत विद्यालय निर्धारित मैन्यू का अनुपालन करते हैं, जबकि 52 प्रतिशत विद्यालय निर्धारित मैन्यू का अनुपालन नहीं करते हैं और 74 प्रतिशत विद्यालयों के बच्चों ने स्पष्ट रूप से मध्याह्न भोजन की मात्रा के प्रति असंतोष जाहिर किया।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की अवधारणाएँ

1. सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें उपलब्ध हैं।
2. सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध हैं।
3. सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों की स्थिति समान है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए "वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि" का प्रयोग किया गया है।

क्र० सं०	भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों के अवलोकन बिन्दु का विवरण	क्र० सं०	भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों के अवलोकन बिन्दु का विवरण
1.	शिक्षक छात्र अनुपात (1:40)	8.	पुस्तकालय की व्यवस्था
2.	उचित श्यामपट्ट सुविधा	9.	फर्नीचर की व्यवस्था
3.	शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था	10.	सवातन की सुविधा
4.	उचित पेयजल व्यवस्था	11.	प्रकाश की उचित व्यवस्था
5.	शौचालय की व्यवस्था	12.	मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था
6.	खेल का मैदान	13.	स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम
7.	उत्तम विद्यालय भवन	14.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
		15.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक

सांख्यिकीय प्रविधि

अध्ययन के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सांख्यिकीय प्रविधि में प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सर्वशिक्षा अभियान के भौतिक सुविधाओं एवं शैक्षिक सुविधाओं से सम्बन्धित मानकों के आधार पर शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन।

शिक्षक छात्र अनुपात

सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता द्वारा हाथरस जिले के दो ब्लॉक— हाथरस ब्लॉक एवं सासनी ब्लॉक में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों एवं कार्यरत् अध्यापकों के अनुपात का अध्ययन किया गया। इस सन्दर्भ में प्रयुक्त अवलोकन सूची के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

जनसंख्या एवं न्यादर्श का चयन

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया। सर्वशिक्षा अभियान के निर्धारित मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति के अध्ययन के लिए हाथरस जनपद के दो ब्लॉक— हाथरस ब्लॉक एवं सासनी ब्लॉक से कुल 50 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को चयनित किया गया। जिसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को क्षेत्र के आधार पर शहरी (15), अर्द्धशहरी (15) व ग्रामीण (20) तीन वर्गों में विभाजित किया गया।

अध्ययन के उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन के सन्दर्भ में सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर विद्यालयों की स्थिति हेतु विद्यालयों में भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए स्व-निर्मित अवलोकन सूची का निर्माण किया गया। जिसमें 15 बिन्दुओं के आधार पर अवलोकन सूची का निर्माण किया गया जिसमें सूची और मानक/विषय बिन्दु क्रमशः हैं।

तालिका 1.1 क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात की स्थिति

प्राथमिक विद्यालय	1:40 से कम प्रतिशत	1:40 के बराबर प्रतिशत	1:40 से अधिक प्रतिशत
शहरी	40	40	20
अर्द्धशहरी	20	40	40
ग्रामीण	0	20	80
कुल	20	33.3	46.66

परिणाम विश्लेषण

उपरोक्त तालिका 1.1 से स्पष्ट है, कि— प्राथमिक विद्यालयों में केवल 33.3 प्रतिशत शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित मानक (1:40) के अनुरूप है। जिसमें शहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में से केवल 20 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में ही शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित मानक (1:40) के अनुरूप है। प्राथमिक विद्यालयों में 46.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित मानक (1:40) से अधिक है। जिसमें शहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 20 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में से

E: ISSN No. 2349-9435

40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में से 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित मानक (1:40) से अधिक है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि हाथरस जिले में 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित मानक के अनुरूप या मानक (1:40) से अधिक को देखते हुए काफी सन्तोषजनक है।

विद्यालयों में श्यामपट्ट सुविधा एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था

उक्तमानको/विषय बिन्दुओं के लिए अध्ययनकर्ता द्वारा प्रयुक्त अवलोकन सूची के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

तालिका 1.2 क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था

प्राथमिक विद्यालय	उचित श्यामपट्ट सुविधा प्रतिशत	शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था प्रतिशत
शहरी	80	40
अर्द्धशहरी	60	20
ग्रामीण	50	20
कुल	63.33	26.66

परिणाम विश्लेषण

उपरोक्त तालिका 1.2 से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों के 63.33 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उचित श्यामपट्ट सुविधा है। 26.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था है। जिसमें शहरी प्राथमिक विद्यालयों से 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों तथा अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 60 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उचित श्यामपट्ट सुविधा है। “ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में से केवल 50 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में ही उचित श्यामपट्ट सुविधा है। 40 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 20 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में एवं 20 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में ही शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था है।” निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उचित श्यामपट्ट सुविधा एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था के संदर्भ में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति शहरी एवं अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों के अपेक्षा निम्न है।

विद्यालयों में उचित पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था

उक्त मानकों/विषय बिन्दुओं के लिए प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

तालिका 1.3 क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत प्राथमिक विद्यालयों में उचित पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था

प्राथमिक विद्यालय	उचित पेयजल की व्यवस्था प्रतिशत	शौचालय की व्यवस्था प्रतिशत
शहरी	100	80
अर्द्धशहरी	80	60
ग्रामीण	60	50
कुल	80	63.33

परिणाम विश्लेषण

उपरोक्त तालिका 1.3 से स्पष्ट है कि प्राथमिक

Periodic Research

विद्यालयों में से 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उचित पेयजल की व्यवस्था पायी गई एवं 63.33 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था चालू स्थिति में पायी गई। जिसमें शहरी प्राथमिक विद्यालयों में 100 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उचित पेयजल व्यवस्था पायी गई, एवं ग्रामीण विद्यालयों में से 60 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उचित पेयजल व्यवस्था है। 80 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों 60 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालय में शौचालय चालू स्थिति में थे एवं 50 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था चालू स्थिति में पायी गई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था सन्तोषजनक है परन्तु पूर्ण सन्तोषजनक स्थिति नहीं पायी गयी। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में आज भी ये सुविधायें संतोषजनक स्थिति में नहीं हैं।

विद्यालयों में खेल का मैदान एवं उत्तम विद्यालय भवनों की व्यवस्था

उक्त मानकों/विषय बिन्दुओं के लिए प्रयुक्त अवलोकन सूची के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

तालिका 1.4 क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत प्राथमिक विद्यालयों में खेल के मैदान एवं उत्तम विद्यालय भवनों की स्थिति

प्राथमिक विद्यालय	खेल का मैदान प्रतिशत	उचित विद्यालय भवन प्रतिशत
शहरी	40	60
अर्द्धशहरी	60	60
ग्रामीण	70	40
कुल	56.66	53.33

परिणाम विश्लेषण

उपरोक्त तालिका 1.4 से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में से 56.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त खेल के मैदान की व्यवस्था है। 53.33 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय भवनों की उत्तम स्थिति पाई गयी। शहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में, अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 60 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में से 70 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में खेल के मैदान उपलब्ध थे। 60 प्रतिशत शहरी और अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में केवल 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उत्तम विद्यालय भवन उपलब्ध हुए। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि खेल के मैदान के संदर्भ में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय शहरी एवं अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों से उच्चकोटि के हैं परन्तु विद्यालय भवनों की स्थिति के संदर्भ में निम्नकोटि के हैं।

विद्यालयों में पुस्तकालय एवं फर्नीचर व्यवस्था

उक्त मानकों/विषय बिन्दुओं के लिए प्रयुक्त अवलोकन सूची के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

E: ISSN No. 2349-9435

तालिका 1.5 क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय एवं फर्नीचर की व्यवस्था

प्राथमिक विद्यालय	पुस्तकालय की व्यवस्था प्रतिशत	फर्नीचर की व्यवस्था प्रतिशत
शहरी	40	60
अर्द्धशहरी	40	40
ग्रामीण	10	30
कुल	30	43.33

परिणाम विश्लेषण

उपरोक्त तालिका 1.5 से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में से केवल 30 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था है। 43.33 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में बैठने के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था है। शहरी एवं अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 40 प्रतिशत शहरी एवं अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था पायी गई जबकि ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में से केवल 10 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था है। 60 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में तथा 40 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में 30 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में बैठने के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि—अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय एवं फर्नीचर की व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं है। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति शहरी एवं अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में दयनीय है।

विद्यालयों में सवांतन (पंखे) एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था

उक्त मानकों/विषय बिन्दुओं के लिए प्रयुक्त अवलोकन सूची के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

तालिका 1.6 क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत प्राथमिक विद्यालयों में सवांतन एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था

प्राथमिक विद्यालय	सवांतन की सुविधा (पंखे) प्रतिशत	प्रकाश की उचित व्यवस्था प्रतिशत
शहरी	60	80
अर्द्धशहरी	60	60
ग्रामीण	20	40
कुल	46.66	60

परिणाम विश्लेषण

उपरोक्त तालिका 1.6 से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में से केवल 46.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में सवांतन हेतु पंखों की उचित व्यवस्था है। 60 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में प्रकाश हेतु खिड़की व दरवाजे आदि की उचित व्यवस्था है। शहरी प्राथमिक विद्यालयों एवं अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 60 प्रतिशत शहरी एवं अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में से 20 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में सवांतन हेतु पंखों की व्यवस्था है। 80 प्रतिशत शहरी तथा 60 प्रतिशत अर्द्धशहरी विद्यालयों में प्रकाश हेतु खिड़की, दरवाजे एवं बल्ब आदि की उचित व्यवस्था पायी गई। केवल 40 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में प्रकाश हेतु खिड़की एवं दरवाजों आदि की उचित व्यवस्था है।

Periodic Research

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सवांतन हेतु पंखों एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था के सन्दर्भ में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय शहरी एवं अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अतः स्थिति असन्तोषजनक है।

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

उक्त मानकों/विषय बिन्दुओं के लिए प्रयुक्त अवलोकन सूची के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

तालिका 1.7 क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

प्राथमिक विद्यालय	मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था प्रतिशत	स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम प्रतिशत
शहरी	60	40
अर्द्धशहरी	40	20
ग्रामीण	40	0
कुल	46.66	20

परिणाम विश्लेषण

उपरोक्त तालिका 1.7 से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में से 46.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था है एवं 20 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 60 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में तथा 40 प्रतिशत अर्द्धशहरी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था है, जबकि ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में से 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था पायी गई। 40 प्रतिशत शहरी विद्यालय में व 20 प्रतिशत अर्द्धशहरी विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जबकि किसी भी ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है। इस स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं कि अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था नहीं है एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों पर तो प्राथमिक विद्यालयों में सरकार ध्यान नहीं देती है।

विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की सुविधा

उक्त मानकों/विषय बिन्दुओं के लिए प्रयुक्त अवलोकन सूची के आधार पर प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

तालिका 1.8 क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की सुविधा

प्राथमिक विद्यालय	SC एवं ST के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति सुविधा प्रतिशत	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सुविधा प्रतिशत
शहरी	80	80
अर्द्धशहरी	60	40
ग्रामीण	60	50
कुल	66.66	56.66

परिणाम विश्लेषण

उपरोक्त तालिका 1.8 से स्पष्ट है, कि प्राथमिक विद्यालयों में से 66.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। जिसमें शहरी प्राथमिक विद्यालयों में 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में से 60 प्रतिशत तथा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में से 60 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्राथमिक विद्यालयों में 56.66 प्रतिशत में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें शहरी प्राथमिक विद्यालयों में 80 प्रतिशत, अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में 40 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत ग्रामीण विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी जाती है। शहरी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति मानकों के अनुरूप सन्तोषजनक पायी गई।

अध्ययन के परिणाम

सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करने के सन्दर्भ में

1. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राथमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें से 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उचित पेयजल की व्यवस्था पायी गई।
2. 63.33 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था चालू स्थिति में पायी गई।
3. 56.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त खेल के मैदान की व्यवस्था पायी गई।
4. 53.33 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय भवनों की उत्तम स्थिति पायी गई।
5. 43.33 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में बैठने के लिए उत्तम फर्नीचर व्यवस्था पायी गई।
6. 46.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में संवातन हेतु पंखे, खिड़की, दरवाजों की उचित व्यवस्था पायी गई।
7. 60 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में प्रकाश की उचित व्यवस्था पायी गई।
8. 46.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था पायी गई।
9. 20 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करने के सन्दर्भ में

1. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें से केवल 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित मानक (1:40) के अनुरूप या इससे अधिक पाया गया।
2. 63.33 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में उचित श्यामपट्ट की सुविधा पायी गई।
3. 26.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था पायी गयी।
4. 30 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था पायी गई।

Periodic Research

5. 66.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जाती है।

6. 56.66 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध करायी जाती है।

सर्वशिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें-

1. शिक्षक-छात्र अनुपात के सन्दर्भ में केवल 60 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालय, 80 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालय एवं 100 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय निर्धारित मानक या मानकों से अधिक अनुपात के अनुरूप पाये गए।
2. 80 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 60 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 50 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट सुविधा उत्तम पायी गयी।
3. 40 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 20 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 20 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री की उचित व्यवस्था पायी गई।
4. 100 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 80 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 60 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में उचित पेयजल की व्यवस्था पायी गयी।
5. 80 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 60 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 50 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की उत्तम व्यवस्था पायी गयी।
6. 40 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 60 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 70 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त खेल का मैदान पाया गया।
7. 60 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 60 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 40 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय भवनों की उत्तम स्थिति पाई गयी।
8. 40 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 40 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 10 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई।
9. 60 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 40 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 30 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में बैठने के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था पायी गई।
10. 60 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 60 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 20 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में संवातन हेतु पंखों की उचित व्यवस्था पाई गई।
11. 80 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 60 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 40 प्रतिशत

E: ISSN No. 2349-9435

- ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में प्रकाश की उचित व्यवस्था पाई गई।
12. 60 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 40 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में 40 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था पाई गई।
 13. 40 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 20 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जबकि ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाता है।
 14. 80 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 60 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में व 60 प्रतिशत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जाती है।
 15. 80 प्रतिशत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में, 40 प्रतिशत अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों में एवं 50 प्रतिशत ग्रामीण विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है।

निष्कर्ष

सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधा के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, खेल के मैदान की उत्तम व्यवस्था पाई गई जबकि विद्यालय भवनों, प्रकाश की व्यवस्था, फर्नीचर व्यवस्था, संवातन हेतु सुविधा, मध्याह्न भोजन व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय निम्न स्थिति के पाए गए। शैक्षिक सुविधाओं से सम्बन्धित उपलब्धियों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधा के अन्तर्गत श्यामपट्ट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सुविधा उत्तम पाई गई व शिक्षक-छात्र अनुपात, शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तकालय व्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति निम्न पाई गई। भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं से सम्बन्धित उपलब्धियों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश प्राथमिक विद्यालय निम्न स्तर के हैं। शहरी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अर्द्धशहरी व ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति से अच्छी है व अर्द्धशहरी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों से अच्छी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, जे0सी0 (1987), 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के क्रियान्वयन के संदर्भ में भारतीय शिक्षा की समस्याएँ', अजय प्रिन्टर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली।
2. कपिल, एच0 के0 (2001), 'अनुसंधान विधियाँ', भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. काण्डपाल, के0 (2015), जनपद बागेश्वर में पारंपरिक शिक्षा की दशा एवं दिशा (शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में), भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन0सी0ई0आर0टी0, वर्ष 35, अंक 3, जनवरी 2015, पृ0सं0 45-55।

Periodic Research

4. कोलिस, जे0एम0 (2005), "किण्डरगार्टन विद्यालयों में उपलब्ध विद्यालयी सुविधा का सर्वेक्षण", डिजिटेशन एब्सट्रेक्ट इंटरनेशनल, वॉल्यूम 19।
5. कोहली, वि0 के0 (1975), 'भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्याएँ', कृष्णा ब्रादर्स चॉक अड्डा टाडा, जालन्धर।
6. कौल, एल0 (1984), 'शिक्षा अनुसंधान की कार्यप्रणाली', विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली।
7. चन्द्र, एन0 (2011), 'प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रभावकारिता का अध्ययन, शोध प्रबन्ध, पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र, एम0जे0आर0वि0वि, बरेली।
8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2005-06), एनुअल रिपोर्ट 2005-06 'डिपार्टमेंट ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन एण्ड लिटरेसी', मानव विकास संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. वर्मा, बी0के0 (2014), 'सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति का अध्ययन, परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ, वर्ष 21, अंक 1, अप्रैल 2014, पृ0सं0 101-110।
10. बुच, एम0वी0 (1991), 'फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन', एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
11. बेस्ट, जे0डब्ल्यू0 (1963), 'रिसर्च इन एजुकेशन', प्रिन्टिंग हॉल ऑफ इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली।
12. न्यूपा (2006), एलीमेंट्री एजुकेशन इन इण्डिया, प्रोग्रेस टुवर्ड्स यू.ई.ई., फ्लैश स्टैटिस्टिक्स (2005-06), डी. आई.एस.ई., नई दिल्ली, न्यूपा।
13. यूनेस्को (2007), एजुकेशन फॉर ऑल- द क्वालिटी इन इम्पेरेटिव, पेरिस, यूनेस्को।
14. सिंह, एन0 (2013), 'सर्व शिक्षा अभियान के मौलिक सिद्धान्तों एवं राष्ट्र के निर्माण में उसका योगदान, परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ, वर्ष 20, अंक 1, अप्रैल 2013, पृ0 सं0 79-88।
15. सिंह, एस0पी0 (2013), 'बुनियादी शिक्षा की प्रासंगिकता, परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ, वर्ष 20, अंक 3, दिसंबर 2013, पृ0सं0 61-70।
16. त्रिपाठी, वी0एन0 एवं अमन, ए0के0 (2012) 'सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त विशेष अध्यापकों का विकलांग बालकों की शिक्षा में योगदान, परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ, वर्ष 19, अंक 2, अगस्त 2012, पृ0सं0 35-48।
17. www.eric.ed.gov.com.